विवरण

दिल्ली में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गए/किए जा रहे उपाय :

1. दिल्ली के परिवहन विभाग ने वैज्ञानिक विधि से चालक प्रशिक्षण देने के लिए एक मोटर चालन (ड्राइविंग) प्रशिक्षण स्कूल खोला है।

2. चालन-लाइसेंसिंग तथा वाहनों की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

3. चालकों के लिए नवम्बर, 1992 में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे जो अभी भी जारी हैं। चालकों की प्रवीणता की परीक्षा ली जाती है। इसके अतिरिक्त, सॉसप्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन (इंडिया) नई दिल्ली ने भी चालकों के लिए इंस्पेक्शन पिट, बुराड़ी, नई दिल्ली में 60 एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें, लगभग 6500 चालकों ने भाग लिया।

4. दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) यातायात संबंधी नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करना।

(ii) खतरनाक तरीके से तथा लापरवाही से वाहन चलाने, लाइसेंस बगैर वाहन चलाने शराब पीकर वाहन चलाने और लालबत्ती पार करने के खिलाफ विशेष अभियान।

(iii) उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी करके उनका नियमित रूप से अभियोजन।

(iv) दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में यातायात संकेत/ब्लिंकर लगाना।

(v) दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में और अधिक यातायात पुलिस कर्मी तैनात करना;

(vi) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष गश्ती जांच।

(vii) अल्कोमीटर और रडार गन जैसे अति आधुनिक उपस्करों के माध्यम से अभियोजन।

(viii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए चलती-फिरती प्रदर्शनी वैन को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाना।

(ix) सड़क सुरक्षा संबंधी साहित्य का वितरण।

Bombay-Vadodara Express way Project

1316. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether foreign assistance for conducting detailed engineering of the proposed Bombay-Vadodara Expressway Project was approved by Government;

(b) if so, the amount of loan approved and the terms on which it has been sanctoned; and

(c) the present status of the work and by when it is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) The Asian Development Bank has agreed to provide a loan assistance of US $ 12.7 million for conducting detailed engineering of the proposed Bombay-Vadodara Express way Project. But the loan agreement is yet to be signed with the Bank.

(c) The work is yet to commence and it is too early to indicate the likely date of its completion.

Collection of toll by the Central Government in Gujarat

1317. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what are the bridges in Gujarat where toll is collected by the Central Government;

(b) what were the proceeds from such toll collections during the years 1991-92, 1992-93 and 1993-94; and

(c) what is the further period for which the toll would be collected by the Central Government in Gujarat State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) At present, there is only one bridge in Gujarat on National Highway No. 8 on river Narmada near Zadeshwar where fee is collected by the Union Government.

(b) The proceeds from this bridge during the last three years are as under:-

Year	(Rs. in lakhs)
1991-92	287.56
1992-93	356.48
1993-94	487.23

(c) The fee is levied until the total cost of construction (including interest, cost of approaches/toll plaza and maintenance) is fully realised. It is not possible to indicate the period as this depends upon the volume of traffic.

"बाई-पास" के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश को धनराशि का आवंटन

1318. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1993-94 और वर्ष 1994 की प्रथम छमाही के दौरान "बाई-पासों" के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार उक्त "बाई-पासों" के निर्माण के लिये कब तक धन राशि का आवंटन कर देगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई पासों से है । राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित सभी निर्माण कार्यों तथा इन राजमार्गों पर बाईपासों के निर्माण की जिम्मेदारी मुख्यतः संघ सरकार की है । इसलिये वित्तीय सहायता का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है । तथापि, 1993-94 के दौरान, शिवनाथ नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल तथा उसके पहुंचमार्गों, जो दुर्ग कस्बे के लिये बाई पास भी हैं, के निर्माण के लिये प्राक्कलन प्राप्त हुये हैं । इस पूरी परियोजना हेतु 29.12 करोड़ रु० के लिये प्रशासनिक अनुमोदन जुलाई, 94 में पहले ही जारी कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) 1994-95 के लिये मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और बाईपासों के विकास के लिये 1450.00 लाख रु० आवंटित किये गये हैं ।

Setting up an Indian Maritime University

1319. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to establish an autonomous body designated as Indian Martime University;